Seventeenth Loksabha

>

Title: Demand to help Beedi workers of Telangana and to rectify the e-nomination problems in Provident Fund Scheme.

श्री अरविंद धर्मापुरी (निजामाबाद): बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी । मैं तेलंगाना से आता हूं और तेलंगाना में तकरीबन 10 लाख बीड़ी वर्कर्स रहते हैं और इसमें से 98 प्रतिशत महिलाएं हैं । उनमें 90 प्रतिशत अशिक्षित हैं । उनके नामों में डिस्क्रिपेंसी है । उनके प्रॉविडेंट फंड के फॉर्म-9 और आधार कार्ड में डिस्क्रिपेंसी है । शादी से पहले सर नेम अलग होता है और शादी के बाद सर नेम चेंज होता है या आधार के रजिस्ट्रेशन के समय डेट ऑफ बर्थ की गलत एंट्री हो जाती है । इन छोटी-छोटी डिस्क्रिपेंसीज की वजह वे प्रॉविडेंट फंड विड्रा नहीं कर पा रही हैं । इसलिए सरकार ने 30 नवम्बर तक का समय डिसक्रिपैंसीज़ ठीक करने के लिए दिया है । तेलंगाना में महिलाओं की बड़े पैमाने पर इस तरह की समस्या है । इसके लिए यह समय कम पड़ेगा, इसलिए मैं मंत्री जी से सुबह मिला था । उन्होंने तुरन्त तीन महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं । इसके अलावा आधार के रेक्टिफिकेशन सेंटर की बात है । अगर तीन महीने में हमें दस लाख लोगों को कवर करना है तो वहां सेंटर्स की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है ।

महोदय, हमारे यहां बीड़ी वर्कर्स को डेढ़ लाख रुपये अलग स्कीम से इससे पहले घर बनाने के लिए दिए जाते थे । अब उसे आवास योजना में मिला दिया गया है । लेकिन आवास योजना का पैसा सरकार द्वारा जो दिया जाता है, उसको डायवर्ट कर दिया जाता है । इसलिए वहां की महिलाएं, बीड़ी वर्कर्स बहुत गरीब हैं, उनको एक भी घर आवास योजना से नहीं दिया गया है । आज तक पांच सौ घर भी हेण्डओवर नहीं किए गए हैं । फण्ड का डायवर्जन ज्यादा हो रहा है । इसलिए मैं यह सरकार की दृष्टि में लाना चाहता हूं कि इंटिग्रेटिड हाउसिंग स्कीम के तहत बीड़ी वर्कर्स को घर बनाने के लिए दूसरी योजना के तहत कुछ किया जाना चाहिए, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं । धन्यवाद ।